आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 07.12.2025 समय : 1905

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल लोकसभा में वंदे मातरम की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कहा कि देश वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए कल से अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
- अंडमान निकोबार मुक्केबाजी संघ की ओर से विभिन्न श्रेणियों के लिए बीस और इक्कीस दिसम्बर को चैंपियनशिप–सह–चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह इस बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि पूरे दिन की चर्चा दोपहर बारह बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आठ दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा और नौ दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कहा कि देश उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है जो अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन, दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस लोगों की रक्षा करता है और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि सैनिकों का कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। श्री मोदी ने देशवासियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बधाई दी। श्री चौहान ने भारत की रक्षा तैयारियों

और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी दृढ़ सेवा, अदम्य साहस और निरंतर योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी सीमाओं और क्षेत्रों में राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान किया।

<><><><><><><>

वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को इस महीने की छह तारीख को अपलोड के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि उम्मीद अधिनियम उन्नीस सौ पचानब्बे और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार पोर्टल ने छह महीने की अपनी समय सीमा पूरी कर ली है। मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल पर पांच लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया, जबकि दो लाख से अधिक संपत्तियों को नामित अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्माताओं द्वारा दो लाख तेरह हजार से अधिक संपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं और समय सीमा तक विचाराधीन हैं। मंत्रालय ने कहा कि कई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सचिव स्तर पर उच्च स्तरीय हस्तक्षेपों ने इस प्रक्रिया में नई गति प्रदान की है। इस कारण अंतिम समय में अपलोड में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक विभागों के साथ निरंतर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

<><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को द्वीपसमूह के स्थानीय निवासियों के रोज़गार और शिक्षा की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि द्वीपसमूह में लोग भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला पाने के लिए "लोकल सर्टिफिकेट" पर निर्भर रहे हैं। द्वीपों की रणनीतिक कमियों, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित आर्थिक अवसरों पर ज़ोर देते हुए, सांसद ने कहा कि यहां सरकारी नौकरियां और पेशेवर शिक्षा ही सामाजिक विकास के एकमात्र रास्ते हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तर्ज पर द्वीपसमूह में भी "स्थानीय निवासियों" को परिभाषित करने वाला एक कानूनी ढांचा तैयार करने की मांग की है, ताकि इसके आधार पर स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में प्राथमिकता मिल सके।

<><><><><><><>

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र की ओर से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए "द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की तटीय और समुद्री जैव विविधता पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" का

आयोजन किया जाएगा। कल से बारह दिसंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से चौबीस भारतीय वन अधिकारी भाग लेंगे। पाँच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कक्षा शिक्षण के अलावा स्वराज द्वीप, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाटापू जैविक पार्क, बाराटांग में लाइम स्टोन गुफा का दौरा और बूमनेला में अंतर–ज्वारीय समुद्री जैव विविधता पर अध्ययन दौरा शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कल सुबह दस बजे मिनी बे स्थित सी शेल कोरल कोव में होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सचिव जी. बालाचंद्रन उपस्थित रहेंगे।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार मुक्केबाजी संघ की ओर से सीनियर, जूनियर और सब–जूनियर श्रेणियों के लिए बीस और इक्कीस दिसम्बर को मुक्केबाजी राज्य चैंपियनशिप–सह–चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। यह चयन नवीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए किया जाएगा, जो इक्कतीस दिसम्बर से अगले वर्ष छः जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार गूगल फॉर्म के माध्यम से अट्ठारह दिसम्बर शाम पांच बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं।

<><><><><><><>

"संपर्क से समाधान – प्रशासन गांव की ओर" पहल के अंतर्गत रंगत में लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्योत्तर अंडमान जिले के उपायुक्त सुशान्त पाधा ने की। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से शिकायतों का निवारण करना है। राजस्व शिविर न्यायालय के दौरान तेरह उप–विभागीय मामले और अट्ठाईस नाम संशोधन मामले स्वीकृत किये गये। नागरिकों ने सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, राशन आपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं से सम्बंधित मुद्दे उठाये।

<><><><><><><>

पर्यटन मंत्रालय के तहत इंडिया टूरिज्म, ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, स्वराज द्वीप के गोविंद नगर में एक दिवसीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के पर्यटन कर्मियों, विशेष रूप से समुद्री और साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के बीच आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना था। प्रशिक्षण में कुल पचास प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक वेल मुरुगन ने अपने संबोधन में द्वीपों में सुरक्षा मानकों में सुधार तथा कुशल पर्यटन कार्यबल बनाने पर मंत्रालय के ध्यान को रेखांकित किया।

एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्वी क्षेत्र के सह–अध्यक्ष सैकत बिस्वास ने सीमित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और लंबे निकासी समय के कारण अंडमान द्वीप समूह में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

<><><><><><><>